



बिहार विधान परिषद

210वां मॉनसून सत्र

अल्पसूचित प्रश्न

24 जुलाई 2025

[गृह - पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन - योजना एवं विकास - श्रम संसाधन - वित्त विभाग - वाणिज्य कर - मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन - परिवहन - जल संसाधन - लघु जल संसाधन - समाज कल्याण - अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण - पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण].

अल्पसूचित प्रश्नों की कुल संख्या 16

चेकडैम का निर्माण

*45 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के सिरदला प्रखंडान्तर्गत पंचायत खटाँगी में एक प्राकृतिक झरना है, जो दोआरपाल झरना के नाम से जाना जाता है ,जिसका पानी यत्र-तत्र गिरकर बर्बाद हो जाता है;

(ख) क्या यह सही है कि दोआरपाल झरना के पानी को संग्रह कर चेक डैम निर्माण करवा दिया जाए, तो किसानों को कृषि कार्य में काफी सहूलियत होगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडो के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार किसानों के हित में दोआरपाल झरना का पानी संग्रह कर चेकडैम का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कबतक, नहीं तो क्यों ?

सूद सहित भुगतान

***46 श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **वित्त विभाग** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है, कि सहारा इंडिया ने बिहार के 95 लाख निवेशकों से अपने विभिन्न स्कीमों/ योजनाओं में 1.50 लाख करोड़ रुपया का निवेश करवाया है जो आज सूद सहित 2.50 लाख करोड़ हो गया है। जिसके भुगतान हेतु निवेशक 13 वर्षों से दावा पेश कर रहे हैं, लेकिन भुगतान नहीं हो रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि पूरे बिहार में सहारा इंडिया धीरे-धीरे अपना कार्यालय बंद कर रहा है, और निवेशक/ आम जमाकर्ता अपने को ठगा सा महसूस कर रहे हैं;

(ग) क्या यह सही है कि सहारा इंडिया दिन दहाड़े बिहार के 95 लाख निवेशकों का 2.50 लाख करोड़ रुपया गबन कर रहा है, जिसको देखने वाला कोई नहीं है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार राज्य के 95 लाख निवेशकों को उनका पैसा उन्हें वापस कराने हेतु सख्त कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

नहर को जोड़ने की कार्रवाई

***47 श्री कुमार नागेन्द्र (स्थानीय प्राधिकार, जहानाबाद, गया एवं अरवल):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि जहानाबाद जिले में फल्गु नदी पर निर्मित उदेरा स्थान बैराज से गया, जहानाबाद, नालंदा जिला के कुल 41890 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई का लक्ष्य है;

(ख) क्या यह सही है कि उदेरा स्थान बैराज से नई बाजार, इस्लामपुर (मोहन चक) बड़ी पैठना, निश्चलगंज नहर को जोड़ने से गया, जहानाबाद एवं नालंदा जिले के हजारों किसानों की खेती को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने हेतु कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार उदेरा स्थान बैराज से नई बाजार इस्लामपुर (मोहन चक), बड़ी पैठना, निश्चलगंज नहर को जोड़ना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

सुरक्षा व्यवस्था

***48 श्री सौरभ कुमार (पश्चिमी चम्पारण स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **वित्त विभाग** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय लोगों की बैंकिंग सुविधा हेतु सीएसपी (Customer Service Point) केंद्रों का संचालन किया जा रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि ग्रामीण सीएसपी संचालकों को ग्राहकों के लेन देन हेतु नगद राशि की आपूर्ति संबंधित बैंकों द्वारा की जाती है, और इस प्रक्रिया में संचालकों को अपने खर्च पर नगद राशि लानी होती है, जिसके दौरान लूटपाट, डकैती और हत्या जैसी घटनाएं घटित होती रहती है;

(ग) क्या यह सही है कि वर्तमान में अधिकांश बैंकों द्वारा सीएसपी संचालकों हेतु किसी प्रकार का दुर्घटना बीमा या सुरक्षा कवर लागू नहीं किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सभी बैंकों को अपने अधीन कार्यरत सीएसपी संचालकों के लिए दुर्घटना बीमा और सुरक्षा व्यवस्था लागू कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

सुलिस गेट का निर्माण

***49 श्री मो. सोहैब (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि समस्तीपुर जिलान्तर्गत रोसड़ा प्रखण्ड के पंचायत रहुआ वार्ड नं -09 में अवस्थित मंदिर के सामने बुढ़ी गंडक नदी पर बने बांध के किनारे बसे लोगों को बरसात के दिनों में मुहल्ले के जल निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों का जीवन अस्तव्यस्त हो जाता है;

(ख) यदि उपर्युक्त खण्ड (क) का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार जनहित में रोसड़ा प्रखण्ड के पंचायत रहुआ वार्ड नं -09 में अवस्थित मंदिर के सामने मुहल्ले में जल जमाव से हो रही दिक्कतों के समाधान हेतु बुढ़ी गंडक नदी के किनारे बने बांध पर सुलिस गेट का निर्माण कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक ?

रिवर फ्रंट के निर्माण

***50 डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि सुपौल शहर से गजना नदी गुजरती है, जो मृतप्राय हो गई है;

(ख) क्या यह सही है कि सुपौल में आम आदमी के सुबह की सैर के लिए कोई बड़ा पार्क नहीं है। गजना नदी के किनारे बी० एस० एस० कॉलेज के पीछे "रिवर फ्रंट " विकसित कर शहरवासियों को सुबह की सैर और सुकून के पल बिताने के लिए एक उत्तम व्यवस्था की जा सकती है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उपर्युक्त वर्णित स्थल या गजना नदी किनारे या अन्य स्थल पर "गजना रिवर फ्रंट" का निर्माण करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

बसों का ठहराव

***51 श्री रवीन्द्र प्रसाद सिंह (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **परिवहन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि पटना नगर के विभिन्न मुख्य पथों पर नगर विकास विभाग द्वारा जगह -जगह पूर्व से ही बस ठहराव की व्यवस्था की गई है;

(ख) क्या यह सही है कि पूर्व से निर्मित बस स्टॉप पर बसों का ठहराव नहीं होता है;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पटना नगर के बस स्टॉप पर बसों का ठहराव सुनिश्चित कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

फर्जी निबंधन पर रोक

***52 प्रो. संजय कुमार सिंह (तिरहुत शिक्षक):**

क्या मंत्री, **मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि गया जिले के समाहर्ता गया के पत्रांक- 245/भू.रा., दिनांक 30.07.2021 द्वारा मौजा कंडी स्थित भूमि के खाता -148, खेसरा- 1187 पर स्थगन आदेश पारित है;

(ख) क्या यह सही है कि स्थगन आदेश पारित रहने के बावजूद फर्जी व्यक्तियों के द्वारा उक्त भूमि की फर्जी बिक्री करने का प्रयास किया जा रहा है;

(ग) क्या यह सही है कि दिनांक- 28.04.2025 को निबंधित स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला पदाधिकारी, गया एवं जिला अवर निबंधक, गया से उक्त भूमि की बिक्री पर रोक लगाने हेतु सभी साक्ष्यों के साथ श्री राम बाबू द्वारा आवेदन समर्पित किया गया है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो सरकार खंड 'क' में वर्णित भूमि के फर्जी निबंधन पर रोक लगाने हेतु जिला अवर निबंधक गया को निर्देश देना चाहती है?

इलेक्ट्रिक बस का परिचालन

***53 श्री मो. फारूक (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **परिवहन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार राज्य परिवहन निगम की इलेक्ट्रिक बसें पटना से सीतामढ़ी आने-जाने के लिए परिचालन नहीं होने के कारण यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार पटना से सीतामढ़ी के लिए जनहित में सुबह-शाम इलेक्ट्रिक बसें चलाना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

कानून सम्मत कार्रवाई

***54 डा. प्रमोद कुमार (मनोनीत):**

क्या मंत्री, **गृह** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के मधेपुर थाना कांड संख्या-58/12 के प्राथमिक अभियुक्त श्री उदय शंकर तिवारी को जेल भेजा गया था, एवं इन पर मधेपुर थाना कांड संख्या-99/23 में दर्ज प्राथमिकी अनुसंधान में सत्य पाई गई है;

(ख) क्या यह सही है कि श्री तिवारी ग्रामीणों को भयादोहन कर पैसा उपार्जित करते हैं, और जो पैसा नहीं देता है उसके विरुद्ध झंझारपुर व्यवहार न्यायालय में मुकदमा दायर कर तंग-तबाह करने की कोशिश करते हैं;

(ग) क्या यह सही है कि श्री तिवारी के असामाजिक आचरण के कारण इस क्षेत्र में अशांति पैदा हो गई है;

(घ) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार श्री तिवारी के असामाजिक आचरणों की जांच आरक्षी अधीक्षक, मधुबनी से कराकर इनके विरुद्ध कानून सम्मत कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

पुल का निर्माण

***55 डा. उर्मिला ठाकुर (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि मधुबनी जिला के बेनीपट्टी प्रखण्ड व बिहार विधान सभा क्षेत्र सं०-32 (बेनीपट्टी) के अन्तर्गत केशुली ग्राम में वधराजा नदी के दोनों ओर से क्षेत्रों में

हजारों एकड़ जमीन पर खेती कार्य हो रही है;

(ख) क्या यह सही है कि केशुली ब्रह्मस्थान से उक्त नहरी पार करते हुए सर्वे रास्ता केशुली नगवास, करही, नवकरही होते हुए अर्डर के मुख्य सड़क बनी पड़ी- मधुवनी सड़क से मिलती है;

(ग) क्या यह सही है कि उक्त नदी पर के भुली के पास पुल रहने से प्रतिवर्ष नदी पार करते समय पशु एवं मनुष्य का डुबकर मृत्यु हो जाता हैं, फिर भी संबंधित सक्षम पदाधिकारीगण जागरूक नहीं है ;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार लोकहित में खण्ड 'क' पर अंकित नदी व स्थान पर इस वित्तीय वर्ष में पुल निर्माण करना चाहती है, यदि हां तो कब तक ?

एन.ओ.सी कबतक

***56 प्रो. गुलाम गौस (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **योजना एवं विकास** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि स्थानीय एवं संबंधित पदाधिकारियों द्वारा विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन में ससमय अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी) नहीं दिये जाने के कारण अत्यंत विलंब होता है;

(ख) क्या यह सही है कि 9 अप्रैल 2025 को उपमुख्यमंत्री एवं पटना जिला के प्रभारी मंत्री ने अपनी अध्यक्षता में हुई मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना की बैठक में स्पष्ट आदेश दिया है कि संबंधित स्थानीय पदाधिकारी एक माह के अंदर विकास योजना के लिए एन.ओ.सी. देंगे अन्यथा, उनके विरुद्ध जिला पदाधिकारी द्वारा कार्रवाई की जाएगी;

(ग) क्या यह सही है कि पटना जिला के दानापुर अंचल में विभिन्न कब्रिस्तानों सहित मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत अनेकों योजनाओं के लिए संबंधित पदाधिकारी द्वारा एक साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद एन.ओ.सी. नहीं दिया गया है, जिससे विकास कार्य ठप है;

(घ) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार इस संबंध में उचित कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

प्रदूषण पर नियंत्रण

***57 श्रीमती शशि यादव (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नासरीगंज, दानापुर, पटना में भोला राम स्टील कंपनी द्वारा बड़े पैमाने पर धुआँ निकलने के कारण प्रदूषित हवा से स्थानीय निवासी दमा, खांसी, कैंसर आदि जानलेवा बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, क्योंकि फैक्ट्री प्रबंधन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गये शर्त का लगातार उल्लंघन कर रहा है;

(ख) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा पटना जिला में बिहटा, फतुहा, नौबतपुर एवं हाजीपुर (वैशाली) आदि क्षेत्र में फैक्ट्री स्थापित करने के लिए औद्योगिक क्षेत्र बनाये गये हैं ;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार प्रदूषण फैलाने वाले फैक्ट्री को घनी आबादी वाले क्षेत्र नासरीगंज, दानापुर से हटाकर पटना के नजदीक विकसित किये गये औद्योगिक क्षेत्र में शिफ्ट करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों ?

पईन की खुदाई

***58 श्री अशोक कुमार (स्थानीय प्राधिकार, नवादा):**

क्या मंत्री, **लघु जल संसाधन** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि नवादा जिला के रोह प्रखंडान्तर्गत नए पईन की खुदाई कराने हेतु पंचायत सिउर के महादलित टोला से इज्जन नगर होते हुए ग्राम जैला के रजाइन पईन के चारमुहानी तक चार वर्ष पूर्व सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) क्या यह सही है कि नए पईन की खुदाई करा देने से प्रखंड रोहए कौवाकोल एवं पकरीबरावां के कई गाँव के हजारो-हजार एकड़ भूमि सिंचित होगी;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसानों के हित में खेतों के सिंचाई के लिए पूर्व सर्वेक्षण के अनुसार सिउर पंचायत के महादलित टोला से इज्जन नगर होते हुए ग्राम जैला के रजाइन पईन के चारमुहानी तक नई पईन की खुदाई कराना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

दोषी कर्मों के विरुद्ध कार्रवाई

***59 श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी (विधान सभा):**

क्या मंत्री, **समाज कल्याण** विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

दिनांक- 18.06.2025 को "दैनिक भास्कर" समाचार पत्र में प्रकाशित शीर्षक "वृद्धा पेंशन योजना... घपला रोकने के लिए 28 जून तक होगा डोर टू डोर सर्वे" को ध्यान में रखते हुए क्या मंत्री, समाज कल्याण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन एवं मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन का लाभ 60 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को दिया जाता है, लेकिन राज्य में 15 से 25 साल के उम्र के 16 हजार व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ दिया गया है, जो कि आर्थिक अपराध है;

(ख) यदि उपर्युक्त खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो उक्त वर्णित पेंशन घोटाले के लिए विभाग के कौन-कौन पदाधिकारी एवं कर्मचारी दोषी है, और सरकार उनके विरुद्ध कौनसी कार्रवाई करना चाहती है, यदि हां तो कब तक, नहीं तो क्यों?

शस्त्र का नवीकरण

*60 डा. अजय कुमार सिंह (सहरसा स्थानीय प्राधिकार):

क्या मंत्री, गृह विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) क्या यह सही है कि बिहार के अधिकांश जिलों में शस्त्र अनुज्ञप्ति नवीकरण के आवेदन सालों से लम्बित हैं;

(ख) क्या यह सही है कि शस्त्र अनुज्ञप्ति नवीकरण संबंधित जिला शस्त्र पदाधिकारी द्वारा नहीं किये जाने का क्या कारण है, बिहार में नवीकरण के कितने आवेदन लम्बित हैं;

(ग) यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शस्त्र अनुज्ञप्ति नवीकरण आवेदनों के निष्पादन हेतु जिलों को निर्देशित कर नवीकरण की समय सीमा तय करना चाहती है, यदि हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों?

पटना - 800015.

24 जुलाई, 2025.

अखिलेश कुमार झा,
सचिव, बिहार विधान परिषद्